

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 909
दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र

909. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण स्तर का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;
- (ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली तथा महाराष्ट्र के संभाजी नगर (औरंगाबाद) जिले और मुंबई सहित राज्यवार और जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
- (ग) महाराष्ट्र सहित देश भर में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों का ब्यौरा क्या है?
- (घ) दिव्यांग लड़कों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) की संख्या कितनी है?
- (ङ) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान मुंबई में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण स्तर का आकलन करने के लिए समय-समय पर अध्ययन किए गए हैं। इस मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) द्वारा प्रकाशित हाल की कुछ रिपोर्टें इस प्रकार हैं:

- i. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केंद्रों की रिपोर्ट (अप्रैल 2016 - मार्च 2017)
- ii. आईसीडीएस की निगरानी और पर्यवेक्षण (2015-2016)
- iii. आईसीडीएस की निगरानी और पर्यवेक्षण (2014-2015)
- iv. आईसीडीएस में लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का अध्ययन (2014-2015)
- v. केंद्रीय निगरानी इकाई (सीएमयू) परामर्शदाताओं (2013-14) के निगरानी दौरों पर आधारित गुणात्मक रिपोर्ट - असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
- vi. आईसीडीएस योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण 2013-14

निपसिड राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) को प्रशिक्षण प्रदान करता है जो आगे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करते हैं। निपसिड के छह केंद्र हैं जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और पांच क्षेत्रीय केंद्र (i) गुवाहाटी (ii) बेंगलुरु (iii) लखनऊ (iv) इंदौर और (v) मोहाली में हैं।

सरकार ने कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 10 मई, 2023 को पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल शुरू की है तकि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को छह साल से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा तथा पोषण सेवा प्रदान करने की क्षमता बढ़ाई जा सके।

इस मंत्रालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सशक्त बनाने और दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए इष्टतम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत दो पाठ्यक्रम रूपरेखाएं तैयार की हैं - "नवचेतना - यह जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा" और "आधारशिला- यह 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम" है।

दिनांक 27.11.2024 तक पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए प्रोटोकॉल पर देश भर में कुल 23,411 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों) और 37,732 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ड.) और (च): वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए ईसीसीई के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए 324.16 करोड़ रुपये (केंद्रीय अंश) की धनराशि आवंटित की गई है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4.11 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.61 करोड़ रुपये मुंबई सहित महाराष्ट्र को आवंटित किए गए हैं।